रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेय जल

*523. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु धनराशि का आवंटन करने के लिए किन मानदण्डों का अनुसरण किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार उक्त प्रयोजन के लिए निधियों का नियतन करते समय मैदानी क्षेत्रों की तुलना में रेगिस्तानी क्षेत्रों में गांवों के बीच दूरी, कूओं को अत्यधिक गहराई और ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं पर अधिक लागत को ध्यान में रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या राजस्थान के लिए 1979-80 के लिए धनराशि आबंटित करते समय इन बातों का ध्यान में रखा गया था और यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इन महत्वपूर्ण बातों को और इस तथ्य को देखते हुए कि देश में रेगिस्तानी क्षेत्र का 45 प्रतिशत से अधिक भाग इस राज्य में है, राजस्थान को अधिक धनराशि आबंटित करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तथा (ख). गहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेय जल की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और योजना आयोग के साथ विचारविमर्श करने के बाद योजनाओं का निष्पादन करने के लिए निधियों की व्यवस्था राज्य योजनाओं में की जाती है। तथापि, ग्रामीण जल पूर्ति के बारे में क्योंकि राज्य सरकारें समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल देने के कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पिछड़ गई थी, अतः केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के उन समस्याग्रस्त ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय सहायता देकर राज्यों के संसाधनों को बढ़ाने का निर्णय लिया, जिनको 1972 में किए गये सर्वेक्षण के दौरान दूरी, जल की गहराई तथा जल की गुणवत्ता से सम्बन्धित कतिपय मापदण्डों के आधार पर पता लगाया गया था। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उन शेष समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या, जिन्हें जल उपलब्ध कराया जाना है, उन की जनसंख्या और संसाधन अन्तराल, कार्य निष्पादन इत्यादि जैसी अन्य विशेष बातें हैं जिनका निधियों का नियतन करते समय अनुसरण किया जाता है।

(ग) वर्ष 1979-80 के लिए निधियों का नियतन करते समय उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखा गया था। वर्ष 1980-81 में राजस्थान सरकार को 1979-80 की तुलना में अधिक राशि आबंटित की जायेगी।

Sugar Quota for Exporting Countries in 1981

*524. SHRI P. M. SAYEED:
SHRI GHULAM RASOOL KOCHACK:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that sugar quota for exporting countries in 1981 may continue to be suspended as the international price is likely to rule high;

(b) if so, whether the factors responsible are the fall in production of various countries; and

(c) whether this will also result in lower availability in the international market?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BIRENDRA SINGH RAO): (a) Under the International Sugar Agreement-1977 export quotas are suspended when the prevailing prices cross 15 U.S. cents per lb. The prices are presently ruling at substantially higher levels. If the prices similarly remain above the level of 15 U.S. cents per lb. in 1981 also, then it will result in suspension of export quotas in 1981 as well.

(b) Yes, Sir.

(c) Normally it may result in lower availability. The present high prices in the sugar international market however, may encourage some of the exporting countries to improve on their sugar export efforts and the sugar availability in the international market may not be lower at the expected prices.

Target of Food Production in Drought Hit Orissa

*525. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the target of food production fixed for Orissa for 1980-81 out of 135 millions tonnes target fixed for the whole country; and